

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3747 का उत्तर

नासिक-पुणे हाई स्पीड रेल लाइन

3747. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नासिक-पुणे रेल लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण करके रेलमार्गों को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) कई वर्षों से लंबित उक्त रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और
- (ग) उक्त रेल लाइन को शुरू किए जाने के संभावित समय का ब्यौरा क्या है और इसे पूरा करने के लिए क्या कोई लक्ष्य, निर्धारित किया गया है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): पुणे से नासिक पहले ही पुणे-कल्याण-नासिक (265 किलोमीटर) और पुणे-दौंड-अहमदनगर-मनमाड-नासिक (387 किलोमीटर) के रास्ते रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

इस संपर्कता को और बेहतर बनाने के लिए, दौंड-मनमाड (248 किलोमीटर) लाइन के दोहरीकरण कार्य को स्वीकृति दे दी गई है। कुल 248 किलोमीटर में से, 178 किलोमीटर पहले ही कमीशन किया जा चुका है और शेष खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, संपर्कता में सुधार लाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु निम्नलिखित सर्वेक्षणों को स्वीकृति दी गई है।

- नासिक-साईनगर शिरडी के बीच नई दोहरी लाइन (82 किलोमीटर)
- पुणे-अहमदनगर के बीच नई दोहरी लाइन (125 किलोमीटर)
- साईनगर शिरडी-पुनतांबा का दोहरीकरण (17 किलोमीटर)

पुणे और नासिक के बीच सीधे संपर्क के लिए, महाराष्ट्र सरकार (50%) और रेल मंत्रालय (50%) की संयुक्त उद्यम कंपनी महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमआरआईडीसी) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित संरेखण नारायणगांव से गुजर रहा था, जहां नेशनल सेन्टर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिज़िक्स (एनसीआरए), पुणे ने जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरटी) ऑब्जर्वेटरी स्थापित की है। जीएमआरटी के पास 31 देशों (28वें चक्र तक) के उपयोगकर्ता वैज्ञानिक प्रेक्षणों के लिए इसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं। जीएमआरटी ऑब्जर्वेटरी के संचालन पर प्रस्तावित रेल लाइन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण यह संरेखण स्वीकार्य नहीं पाया गया।

इसलिए, अब रेलवे ने उपरोक्त मुद्दों के समाधान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया है। परियोजना को अभी स्वीकृति नहीं मिली है।

रेल परियोजनाओं को स्वीकृति देना भारतीय रेल की एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। रेल अवसंरचना परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं की देनदारियों, धन की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।
